"उच्च शिक्षा में समग्र एवं बहुविषयक पुनर्गठन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया दृष्टिकोण"

श्रीमती युमेनिका वर्मा

सहायक प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र विभाग

सेठ आर. सी. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ. ग.)

Abstract (सार)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समग्र एवं बहुविषयक पुनर्गठन को एक केंद्रीय लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला होती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार तथा बहुआयामी कौशलों की मांग ने उच्च शिक्षा की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली लंबे समय से विषयों के कठोर विभाजन, एकल -विषयक, सीमित लचीलापन और रोजगार से असंगत पाठ्यक्रमों की समस्या पर आधारित रही है, जिसमें विद्यार्थियों को विषय चयन की सीमित स्वतंत्रता प्राप्त थीं। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर, अनुसंधान की कमी तथा कौशल विकास की समस्या उत्पन्न हुई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति(NEP) 2020 इन समस्याओं को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा में समग्र एवं बहुविषयक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देती है। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप रचनात्मक, आलोचनात्मक और नैतिक नागरिक तैयार करने का लक्ष्य रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारंपरिक, विषय सीमित आधारित शिक्षा प्रणाली से हटकर ज्ञान के विविध क्षेत्रों का समन्वय हैं। इसका मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और व्यावहारिक विकास को एक साथ सुनिश्चित करना है, जिससे वह 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा, जहां विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं होगा। विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन कर सकेंगे, जिससे उनकी रचनात्मकता, आलोचनात्मकता सोच और नवाचार क्षमता का विकास होगा। बहु - प्रवेश एवं बहू -

निकास प्रणाली तथा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी व्यवस्थाएं शिक्षा को अधिक लचीला और विद्यार्थी - केंद्रित बनाती है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति शोध, नवाचार और स्थानीय तथा वैश्विक ज्ञान परंपराओं के समन्वय को प्रोत्साहित करती है। शिक्षण -अधिगम प्रक्रिया में कौशल विकास, अनुभवात्मक अधिगम और मूल्य - आधारित शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। यह दृष्टिकोण उच्च शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्ति तक सीमित न रखकर जीवनोपयोगी ज्ञान और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ता है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह नया बहूविषयक और समग्र दृष्टिकोण उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी गुणवत्ता पूर्ण और भविष्य उन्मुक्त बनाकर राष्ट्र के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखती है।

Keywords - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा,समग्र विकास, वैश्विक परिदृश्य।

1• प्रस्तावना :- **भारत के अतीत में समग्र और बहुविषयक को इतने अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है, वास्तव में भारत की शिक्षा के लिए 21 वीं सदी और चौथी औद्योगिक क्रांति में देश का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत 1986 में की गई थी। इसके 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 घोषित की गई जिसे मौजूदा समय में लागू किया जा रहा है। इसमें एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की गई है, जिसमें हर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा न्याय संगत ढंग से मिल सके। NEP 2020 संयुक्त राष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्य-4 के अनुरूप है। इस लक्ष्य में सबके लिए समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन ज्ञानार्जन के अवसरों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के इस मूल सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के साक्षर बना देने और उन्हें अंक ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए या फिर विद्यार्थियों में विवेचनात्मक सोच और समस्या का समाधान खोजने तक ही सीमित ना रहे बल्कि शिक्षा से सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास भी हो, इन्हें सॉफ्ट स्किल कहा जाता है और इनमें सांस्कृतिक चेतना और अनुभूति, दृढ़ निश्चय और विश्वास, टीम भावना, नेतृत्व और संचार जैसे गुणों का विकास भी शामिल है।**

समग्र और बहुविषयक शिक्षा, शिक्षा को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास है, जिसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बीच संबंध बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा परियोजनाओं और नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गुणवत्ता के साथ सुधारी जा रही है जो छात्रों के लिए बेहतर सीखने के अनुभव को बढ़ावा देती है। इसके साथ

ही, इस नई दिशा में शिक्षा के तरीके भी प्राधिकृत हो रहे हैं, जिससे छात्रों को "सीखने की कौशल" को विकसित करने में मदद मिल सकती है और रटने के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय से भारत के समग्र और बहु-विषयक सीखने की एक लंबी परंपरा है, भारत के व्यापक साहित्य में क्षेत्रों के विषयों को मिलाकर। बाणभट्ट की कादंबरी जैसे प्राचीन भारतीय साहित्यक कृतियों के 64 कलाओं या कलाओं के ज्ञान के रूप में एक अच्छी शिक्षा का वर्णन किया है, गणित विज्ञान, व्यावसायिक विषयों, और सॉफ्ट स्किल सहित रचनात्मक मानव प्रयासों की सभी शाखाओं को 'भारतीय कला' माना जाना चाहिए। 'कई कलाओं के ज्ञान' या आधुनिक समय में यह कहा जाता है, कि इस धारणा को अक्सर 'उदार कला ' कहा जाता है जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक होगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के साथ मानविकी और कला को एकीकृत करने वाली स्नातक शिक्षा में शैक्षिक दृष्टिकोण के आकलन ने लगातार सकारात्मक सीखने के परिणाम दिखाएं हैं, जिसमें रचनात्मकता और नवाचार, महत्वपूर्ण सोच और उच्च - क्रम की सोच क्षमता, समस्या- सुलझाने की क्षमताएं शामिल है, सामूहिक कार्य, संचार कौशल और क्षेत्रों में पाठ्यक्रम की महारत, सामाजिक जुड़ाव और नैतिक जागरूकता में वृद्धि, आदि के अलावा सामान्य जुड़ाव और सीखने का आनंद। समग्र और बहु- विषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हीं चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से लाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समग्र और बहुआयामी शिक्षा मानव - बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करने का लक्ष्य रखेंगी। इस तरह की शिक्षा अच्छी तरह से व्यक्तियों को विकसित करने में मदद करेगी, जो कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यवसायिक तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21वीं सदी की क्षमता रखते हैं। इस तरह की एक समग्र शिक्षा, पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों के दृष्टिकोण में होगी।

2• अध्ययन के उद्देश्य :-

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की अवधारणा को समझना।
(2) उच्च शिक्षा में बहुविषयक पुनर्गठन के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करना।
(3) इस दृष्टिकोण से उत्पन्न अवसरों एवं संभावनाओं का अध्ययन करना।

3• शोध पद्धति :-

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णत: द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। शोध के लिए आंकड़ों का संकलन निम्नलिखित स्रोतों से किया गया है :

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के आधिकारिक दस्तावेज

• शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की रिपोर्टें

• नीति आयोग द्वारा प्रकाशित अध्ययन

• विभिन्न शोध पत्र, पुस्तक एवं शैक्षणिक जर्नल्स

• विश्व बैंक एवं यूनेस्को (UNESCO) की चयनित रिपोर्ट

संकलित आंकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा किया गया है।

4• अध्ययन का महत्व और आवश्यकता :-

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे सीमित रोजगार अवसर, अनुसंधान की गुणवत्ता में गिरावट तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बहुविषयक दृष्टिकोण का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इस शोध की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है :

4.1 समग्र व्यक्तित्व विकास: यह छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, जिसमें कला, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाता है, जिससे एक संतुलित और सक्षम नागरिक तैयार होता है।

4.2 बहुविषयक दृष्टिकोण: यह विषयों के बीच की दीवारों को तोड़ता है, जिससे छात्र विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़कर समस्याओं को व्यापक और रचनात्मक रूप से देख पाते हैं जो आज के समय की मांग है।

4.3 लचीलापन और गतिशीलता: अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी व्यवस्थाएं छात्रों को अपनी गति से और कई बार पढ़ाई छोड़ने और फिर से शुरू करने की सुविधा देती है, जिससे शिक्षा सुलभ और व्यक्तिगत हो जाती है।

4.4 21वीं सदी के कौशल: यह महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता, समस्या - समाधान और डिजिटल साक्षरता जैसे कौशलों को विकसित करता है, जो आधुनिक कार्यबल के लिए आवश्यक है।

4.5 अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा: यह अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बड़ा प्रोत्साहित करता है, जिससे छात्र केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले और नए विचार लाने वाले बनते हैं।

4.6 रोजगारपरकता: विविध कौशल और व्यावहारिक अनुभव (इंटर्नशिप के माध्यम से) छात्रों को नौकरी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।

4.7 डिजिटल एकीकरण: यह शिक्षा में प्रौद्योगिकी (जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब) का लाभ उठाता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच सके।

4.8 भारतीय भाषाओं और संस्कृति का सम्मान: यह भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं को शिक्षा का हिस्सा बनाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है।

5· साहित्य की समीक्षा :-

(1) पवन मांडवकर 2025 : भारतीय ज्ञान परंपरा असाधारण रूप से समृद्ध और अनूठी है। इसमें जीवन और विज्ञान, साधारण और पारलौकिक, कर्म और धर्म, साथ ही भोग और त्याग के बीच एक उल्लेखनीय संतुलन मौजूद है। प्राचीन ऋग्वैदिक काल से चली आ रही, भारतीय शिक्षा प्रणाली ने अपने इतिहास में नैतिक, भौतिक, अध्यात्मिक और भौतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी है। साहित्यिक ज्ञान के अलावा, भारतीय ज्ञान प्रणाली में शारीरिक श्रम के महत्व पर भी बल दिया गया है। इतिहास भर में, भारत में निरंतर आध्यात्मिक बंधुत्व, योग और आयुर्वेद के ज्ञान से विश्व को समृद्ध किया हैं। जिसे आज भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपना रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो देश के शैक्षिक ढांचे को आकार देने में भारतीय ज्ञान प्रणाली के महत्व पर बल देती है। आईकेएस भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। आईकेएस को पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए, यह नीति अंतर्विषयक और पारविषयक समझ को बढ़ावा देने, आधुनिक ज्ञान को पारंपरिक ज्ञान के साथ एकीकृत करने और वर्तमान सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करती है। इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा भाव, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, समानता और न्याय जैसे नैतिक मानवीय और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित गणों का संचार करना है। यह नीति मातृभाषा, शारीरिक शिक्षा के महत्व और

शिक्षकों को निस्वार्थ और सर्वज्ञानी मार्गदर्शन के रूप में उनकी भूमिका को भी मान्यता देती है। मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने, भाषा संसाधनों और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा और ज्ञान (आईकेएस) में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। लेकिन इस नीति को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। भविष्य ही बताएगा कि यह सुधार कितना लाभदायक और प्रगति उन्मुख होगा।

(2) संगीता शर्मा प्रो. जयशंकर पांडे - मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के उद्देश्य का विशेष महत्व है, बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, शिक्षा के क्षेत्र में भी यही बात है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के व्यापक लक्ष्य है, बच्चों के भीतर विचार और कर्म की स्वतंत्रता विकसित करना, दूसरों के कल्याण और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन सभी गुणों का समावेश है। यह शोध पत्र उच्च शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 की मुख्य विशेषताओं एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुशीलन में NEP 2020 की भूमिका पर आधारित है। यह शिक्षा नीति अपने आप में अनेक विचारों नए दृष्टिकोणों एवं समग्र शिक्षा प्रणाली को समाहित की हुई है।

(3) मनीष कुमार नामदेव - यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है, जो मुख्यतः शिक्षा नीति 2020 के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत - केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो इसकी परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और लोकचार में परिवर्तन लाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने को तत्पर है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है, तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सृजन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। नई शिक्षा नीति की वास्तविक मुख्य विशेषताओं को दर्शाना चाहता है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ता, इस शोध पत्र के माध्यम से अनेक सुझावों को प्रस्तुत करता है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है।

(4) पूनम मिश्रा शर्मीला यादव - प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल्य आधारित थी, जिसमें गुरुकुल प्रणाली और विश्व प्रसिद्ध "नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय" शामिल थे। मूल्य आधारित शिक्षा नीति सुधार मानव जाति के लाभ के लिए ज्ञान का उपयोग करने का आधार था। प्राचीन भारत में सुश्रुत, आर्यभट्ट, पाणिनि और चाणक्य जैसे ज्ञानी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालिक प्रभाव 10$2 पैटर्न से 53334 में बदलाव है। यह निर्णय तीन दशकों के बाद भारतीय शिक्षा

प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र शिक्षा, भारत - केन्द्रित शिक्षा, ज्ञान आधारित समाज के विकास और ज्ञान आधारित शिक्षा पर जोर देने के साथ भारतीय - मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा दे रही है।

(5) सोनिया शर्मा, प्रो. डॉ. संजीव कुमार - वर्ष 1986 की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लगभग 34 वर्षों के पश्चात भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन 31 जुलाई 2021 से समूचे भारत में हो गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा दर्शन एवं वैदिक विज्ञान के साथ-साथ शिक्षा के आधुनिक स्वरूप एवं तकनीकी आधारित नवीन शैक्षिक मॉडल और शिक्षण अधिगम के प्रारूपों को अपनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने पर बल देती है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे अधिक खास बात यह है कि विद्यार्थी पर ज्ञान थोपने का समर्थन नहीं करती है। यह नीति विद्यार्थी अनुभव आधारित अधिगम पर बल देती है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावना में भारतीय शिक्षा दर्शन के विचारों को समावेशित करने की झलक मिलती है।

6• उच्च शिक्षा में NEP 2020 के मुख्य प्रावधानः-

6.1 **सकल नामांकन अनुपात GER में वृद्धि :** 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 26.3 % (2018) से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य।

3.5 करोड़ नई सीटे जोड़ी जाएगी और संस्थाओं का विस्तार किया जाएगा।

6.2 बहु -विषयकता और समग्र शिक्षा :एकल - धारा वाले संस्थानों को बहु -विषयक बनाने के लिए विलय किया जाएगा।

कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक शिक्षा आदि के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा।

6.3 बहु प्रवेश- निकास प्रणाली :छात्रों को अपनी सुविधा और गति के अनुसार 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 - 4 साल बाद डिग्री के साथ बाहर निकलने का विकल्प मिलेगा।

6.4 **शैक्षणिक बैंक का क्रेडिट (ABC) :**छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप से जमा और संग्रहित करने के लिए एक प्रणाली तैयार की गई है।

6.5 उच्च शिक्षा आयोग (HECI) :नियामक, मान्यता, वित्तपोषण और अकादमिक मानकों के लिए एक एकल निकाय के रूप में उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की गई है।

6.6 अनुसंधान और नवाचार पर जोर :राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना। गंभीर सोच और तार्किक निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करना।

6.7 संस्थागत स्वायत्तता :महाविद्यालयों को स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करना।

6.8 अंतर्राष्ट्रीयकरण :विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी और छात्र/ संकाय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

6.9 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा :स्थानीय भाषाओं में डिग्री पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन देना।

6.10 समावेशिका और पहुंच :सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) के लिए पर्याप्त धन और पहुंच सुनिश्चित करना। दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच में सुधार करना।

7· शिक्षा के क्षेत्र में लाभ (NEP 2020 के संदर्भ में):

7.1 एकीकृत ज्ञान :छात्रों को विभिन्न विषयों को अलग-अलग न पढ़ाकर, आपस में जोड़कर समझने का अवसर मिलता है, जिससे विषय-वस्तु उबाऊ नहीं लगती।

7.2 कौशल विकास :यह छात्रों में तकनीकी कला, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे कई कौशलों का विकास करता है, जो आधुनिक जरूरतों के अनुरूप हैं।

7.3 रोजगार परकता में वृद्धि :इंटर्नशिप, उद्योग-अनुकूल पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन के माध्यम से छात्रों को बेहतर रोजगार मिलता है और वे उद्यमी बनते है।

7.4 नवाचार और रचनात्मकता :यह रचनात्मक और समस्या-समाधान सोच को बढ़ावा देता है, जिससे छात्र नए विचारों को लागू कर पाते हैं।

7.5 बेहतर शिक्षण अनुभव :यह छात्रों को व्यक्तिगत और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं।

7.6 अनुसंधान और विकास :यह अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे तकनीकी प्रगति होती है और आधुनिक चुनौतियों का समाधान होता है।

7.7 गुणवत्ता और समानता :यह तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता, समानता और शासन को बढ़ाता है, जैसा कि NEP 2020 के तहत बताया गया है।

7.8 भविष्य के लिए तैयारी :यह कर्मचारियों (संकाय) और छात्रों को तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य के लिए तैयार करता है।

7.9 सीखने की संस्कृति :संगठन में निरंतर सीखने और सुधार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिससे नवाचार बढ़ता हैं।

8• उच्च शक्षा पर NEP 2020 के प्रभाव : डेटा-आधारित विश्लेषण

8.1 नामांकन एवं सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio GER) शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education AISHE) 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 4.14 करोड़ (2020-21) से बढ़कर 4.33 करोड़ (2021-22) में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जिसमें महिला नामांकन 2.07 करोड़ तक पहुंच गया है। सकल नामांकन अनुपात (GER) 28.4% है, और 15.98 लाख शिक्षकों के साथ 1100 से अधिक विश्वविद्यालय और 42,000+ महाविद्यालय इसमें शामिल है। सकल नामांकन अनुपात (GER) कसी भी देश की उच्च शिक्षा की पहुँच को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

तालिका 1: भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio GER)

वर्ष	GER (%)
2014–15	24.5
2018–19	26.3
2020-21	27.1

2021–22	28.4
लक्ष्य (2035)	**50.0**

स्रोत : अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण(AISHE) रिपोर्ट, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन दर में सुधार हुआ है, किंतु यह अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है। NEP 2020 द्वारा निर्धारित बहुवषयक एवं लचीली शिक्षा प्रणाली इस अंतर को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। बहुविषयक एवं लचीली शिक्षा प्रणाली इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है।

8.2 रोजगार योग्यता एवं कौशल विकास

उच्च शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाना है। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शिक्षा एवं उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर विद्यमान है।

तालिका 2: भारत में स्नातकों की रोजगार योग्यता स्थिति

संकेतक	**प्रतिशत**	
रोजगार योग्य स्नातक	**लगभग 45% कौशल अंतर**	**लगभग 55%**

स्रोत : भारत कौशल रिपोर्ट (India Skills Report)

उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि परंपरागत एकल विषयक शिक्षा प्रणाली रोजगार योग्यता बढ़ाने में पर्याप्त नहीं रही है। इसी कारण NEP 2020 में व्यावसायिक एवं बहुविषयक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।

8.3 अनुसंधान एवं नवाचार पर प्रभाव : संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान एवं नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। NEP 2020 के माध्यम से भारत में भी विश्वविद्यालयों को शोध- आधारित संस्थाओं के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 उच्च शिक्षा को एकल-विषयक से बहुविषयक (Multidisciplinary) और समग्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखती है। इसका उद्देश्य रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके समक्ष अवसंरचनात्मक कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, अंक- आधारित विभाजन, पाठ्यक्रम में लचीलेपन के कार्यान्वयन जैसी चुनौतियां हैं।

9• उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के पुनर्गठन के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:

9.1 संस्थागत पुनर्गठन: एकल-विषयक संस्थानों को बहु- विषयक विश्वविद्यालयों में बदलना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे और संसाधनों में भारी निवेश की आवश्यकता है।

9.2 शिक्षकों की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण की कमी: बहु-विषयक दृष्टिकोण के लिए अंत:विषयक ज्ञान रखने वाले शिक्षकों की भारी कमी है। इसके अतिरिक्त, अस्थाई संकाय (एड हॉग) संस्कृति और स्थायी संकाय की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यूजीसी रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में शिक्षक पद रिक्त है। साथ ही, बहुविषयक शिक्षण के लिए शिक्षकों को नए कौशलों एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

9.3 पाठ्यक्रम लचीलापन : बहु-प्रवेश और बहु-निकास (Multiple Entry-Exit) के साथ अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC) को लागू करना, जो विभिन्न संस्थानों के बीच क्रेडिट हस्तांतरण की अनुमति देता है, तकनीकी और प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण है।

9.4 डिजिटल और ग्रामीण-शहरी अंतर: ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण, ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षण (Blended Learning) को सभी छात्रों तक पहुंचाना एक चुनौती है।

9.5 पाठ्यक्रम एकीकरण और कौशल: कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों को एक साथ एकीकृत करना, साथ ही स्थानीय उद्योग के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

9.6 मूल्यांकन में बदलाव: परीक्षाओं को रटने से हटाकर योग्यता आधारित बनाने के लिए व्यापक मूल्यांकन सुधारों की आवश्यकता है, जो अभी भी पारंपरिक प्रणाली से ग्रस्त हैं।

9.7 वित्तीय संसाधनों की कमी: विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सार्वजनिक शिक्षा व्यय जीडीपी का लगभग 4.1% है, जबकि NEP 2020 इसे 6% तक बढ़ाने की सिफारिश करती है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के अभाव में नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

इन बाधाओं के बावजूद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत की उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

10· सुझाव: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु उपाय :

• उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को चरणबद्ध रूप से जीडीपी के 6% तक बढ़ाया जाए

• शिक्षकों के लिए सतत व्यवसायिक विकास कार्यक्रम लागू किया जाए

• ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाए

• उद्योग -शिक्षा सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान किया जाए

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु स्वतंत्र निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 उच्च शिक्षा में समग्र एवं बहुविषयक पुनर्गठन के माध्यम से भारत को ज्ञान आधारित समाज एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है यदि इस नीति का प्रभावी एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाए, तो यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगी, बल्कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, नवाचारी एवं वैश्विक नागरिक बनने में भी सहायक सिद्ध होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) उच्च शिक्षा में बहुविषयक और समग्र दृष्टिकोण को लागू कर विद्यार्थी -केंद्रित और कौशल -आधारित शिक्षा सुनिश्चित करता है। कार्यान्वयन में प्रशिक्षण, संसाधन और प्रशासनिक सहयोग अनिवार्य है, नीति के दीर्घकालिक परिणाम सकारात्मक और समग्र शिक्षा के अनुकूल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को बेहतर बनाने के लिए, इसकी क्रेडिट आधारित प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करने, मुख्य विषयों पर जोर देने और गैर मुख्य पाठ्यक्रमों को समाप्त करने की आवश्यकता है। यद्यपि इसके कार्यान्वन में अनेक चुनौतियां हैं, परंतु यदि इसे चरणबद्ध, समावेशी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह नीति भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, नवाचारी और मानवीय बना सकती है।

संदर्भ :

1) **भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।**

2) **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. (2021) एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट गाइडलाइन.**

3) **शिक्षा मंत्रालय 2022 अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षणऑल (AISHE) रिपोर्ट.**

4) **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNESCO (2021) साइंस रिपोर्ट द रेस अगेंस्ट**

5) **कुमार, के.(2021) शिक्षा, समाज और नीति नई दिल्ली: ओरिएंटेड ब्लैकस्वांन.**

6) **अग्रवाल, पी. (2022) "बहुविक शिक्षा और NEP 2020", शैक्षिक अध्ययन पत्रिका।**

7) **तिलक, जे. बी. जी.(2020) हायर एजुकेशन इन इंडिया :पॉलिसी एंड पर्सपेक्टिव.**

8) **प्रो. राम सकल पाण्डेय - शैक्षणिक निबंध।**

9) **पवन मांडवकर 2025: भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP- 2020)।**

10) **संगीता शर्मा, प्रो. जयशंकर पांडेय : जून 2020 ह्यूमैनिटीज एंड डेवलपमेंट.**

11) **.मनीष कुमार नामदेव :सितंबर 2024 जनरल का एडवांस और स्कॉलरली रिसर्चस इन एलिट एजुकेशन.**

12) **पूनम मिश्रा, शर्मीला यादव :मार्च 2024 शब्दकोश जनरल आफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स**

13) **सोनिया शर्मा, प्रो. डॉ. संजीव कुमार :दिसंबर 2023 यूनिवर्सल रिसर्च रिपोर्ट्स.**

14) **विभिन्न शोध पत्र एवं शैक्षणिक जनरल्स ।**

15) **टाइम. वर्ल्ड बैंक (2020) एजुकेशन एंड इकोनामिक डेवलपमेंट रिपोर्ट्स.**